रूस के प्रति तुर्की का झुकाव

लेखक - स्टैनली जॉनी (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

18 जुलाई, 2019

"मास्को के साथ रक्षा सौदे को लेकर अंकारा नाटो को नाराज करने का जोखिम उठाने को क्यों तैयार है।"

नवंबर 2015 में, एक तुर्की एफ-16 ने सीरियाई सीमा पर एक रूसी लड़ाकू जेट को मार गिराया था, जिसके बाद मास्को और अंकारा के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन श्री पुतिन ने तुर्की के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। सारी अटकलों को दरकिनार करते हुए उन्होंने शासन विरोधी विद्रोहियों और जिहादियों को हराने एवं सीरिया के मौजूदा संस्थानों को मात देने के अपने रणनीतिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया।

मिस्टर पुतिन की रणनीति तुर्की पर हमला करने की नहीं, बल्कि उस पर जीत हासिल करने की थी। उन्होंने अटलांटिक गठबंधन में दरार का फायदा उठाया, विशेष रूप से अमेरिकी-तुर्की संबंधों में। क्षेत्रीय समीकरणों के विकास ने भी उनकी शर्त का समर्थन किया। 12 जुलाई को, तुर्की द्वारा रूसी बमवर्षक गिराए जाने के साढ़े तीन साल बाद, अमेरिका और नाटो (NATO) की धमकियों और चेतावनियों के बावजूद अंकारा को रूस के सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का पहला बैच मिला है।

एक विडंबना

यह सोवियत काल के बाद के क्रम में एक महत्वपूर्ण क्षण है। तुर्की नाटो का सदस्य है और इनसिरलिक (Incirlik) में अमेरिकी एयरबेस की मेजबानी भी करता है। तुर्की का रणनीतिक स्थान, दक्षिणी यूरोप, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक खेलों में एक मजबूत पकड़ को दर्शाता है।

शीत युद्ध के दौरान, तुर्की सोवियत संघ के खिलाफ अटलांटिक शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण था। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी, अमेरिका ने अंकारा के साथ घनिष्ठ गठबंधन बनाए रखा। लेकिन अब, एक उच्च तकनीक वाली रूसी मिसाइल प्रणाली एक नाटो राष्ट्र के हवाई क्षेत्र की रक्षा करती है। यह एक विडंबना है कि नाटो की अवधारणा रूस की जाँच करना ही है, जो कि शीत युद्ध के कारण पैदा हुआ था।

अमेरिका ने S-400 प्राप्त करने वाले तुर्की पर कई तकनीकी मुद्दों को उठाया है। अमेरिका को यह डर है कि यह सिस्टम नवीनतम रडार-विकसित अमेरिकी बमवर्षक, एफ -35, से डेटा इकट्ठा करने में सक्षम हो जाएगा, जिसे तुर्की ने अमेरिका से खरीदने की बात की है। S-400 सौदे के साथ आगे बढ़ने के तुर्की के फैसले के जवाब में, अमेरिका ने पहले ही तुर्की पायलटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं।

तुर्की का विफल दांव

जब इसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, तब तुर्की ने अमेरिका की उपेक्षा क्यों की? अमेरिकी-तुर्की संबंधों में दरार 2003 के इराक युद्ध के बाद की है, जब अंकारा ने अमेरिकी आक्रमण के लिए एक लॉन्चपैड बनने से इनकार कर दिया था। सीरियाई संकट के दौरान, तुर्की चाहता था कि अमेरिका विद्रोहियों की ओर से सीरिया में हस्तक्षेप करे और असद शासन को उखाड़ फेंकने में मदद करे, लेकिन ओबामा प्रशासन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।

उस समय तुर्की पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए एक विदेशी नीति उपकरण के रूप में अरब स्प्रिंग पर दांव लगा रहा था। उम्मीद यह थी कि इस क्षेत्र में तानाशाही को इस्लामी राजनीतिक दलों (मुस्लिम ब्रदरहुड, जो

वैचारिक रूप से तुर्की के सत्तारूढ़ न्याय और विकास पार्टी के साथ जुड़ा था) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया, खासकर सीरिया में।

सीरियाई संकट के शुरुआती वर्षों में, सीरियाई-तुर्की सीमा, विद्रोहियों और जिहादियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु थी। जब तक तुर्की ने सीमा को बंद करना शुरू किया, तब तक इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने खुद को सीरिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया था। आईएस ने शुरू में सीरियाई सरकारी बलों और विद्रोही समूहों पर हमला किया। लेकिन एक बार जब यह युद्ध के मैदान में पूरी तरह उतर गया, तो यह तुर्की के खिलाफ हो गया।

तुर्की के असफल सीरियाई दांव का एक और परिणाम सीरियाई कुर्द विद्रोहियों का सशक्तिकरण था, जिनका कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ वैचारिक और सैन्य संबंध है और ये दशकों से तुर्की की सेना से लड़ रहे हैं। जब कुर्दों ने युद्ध के मैदान में आईएस का मुकाबला किया, तो अमेरिका ने उन्हें सीधे समर्थन देना शुरू कर दिया। जिसके बाद तुर्की ने सीरिया में सभी पक्षों को खो दिया। यह असद शासन को उखाड़ फेंकने में विफल रहा क्योंकि रूस और ईरान शासन के बचाव में सामने आ गये थे। अंत में, कुर्द विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित सीमा के पार एक सशक्त कुर्दिस्तान है, जिसे तुर्की अपने प्राथमिक शत्रुओं के रूप में देखता है।

तुर्की ने इस नई वास्तविकता को स्वीकार किया। इसने असद शासन से बाहर निकलने की अपनी मांग को छोड़ दिया और अपना ध्यान अपनी सीमा और सीरियाई कुर्दिस्तान के बीच बेहतर बनाने में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि, इसके लिए रूसी और सीरियाई मदद् की जरूरत है, क्योंकि सीरियाई सरकार भी कुर्दों को किसी भी तरह से सशक्त नहीं देखना चाहती है। लेकिन कुर्द आईएस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के साझेदार थे और 2,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक अभी भी सीरियाई कुर्दिस्तान में तैनात हैं। यहाँ तुर्की के हित सीधे अमेरिका से टकराते हैं।

साथ ही अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल थे। अंकारा ने अमेरिका में रहने वाले तुर्की पादरी फेतुल्ला गुलेन को 2016 में श्री एर्दोगन के खिलाफ विफल तख्तापलट की कोशिश के लिए दोषी ठहराया और वह चाहते थे कि उन्हें तुर्की को सौंप दिया जाए। (तुर्की ने श्री गुलेन के लिंक के साथ सीआईए के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया।) अमेरिका ने तुर्की की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। तुर्की भी अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदना चाहता था, लेकिन वाशिंगटन शुरू में इसे अंकारा को बेचने के लिए उत्सुक नहीं था। अब इन सभी मुद्दों के कारण ही तुर्की ने रूस के विकल्प का चुनाव किया।

पुतिन की गणना

श्री पुतिन के लिए, तुर्की एक बड़ी जीत है, जो कि उनके सोवियत मालिकों के पास भी नहीं है। यदि तुर्की इनकी तरफ है, तो बोस्नियास स्ट्रेट के माध्यम से रूस के पास काला सागर (जहाँ इसके नौसेना के अड्डे हैं) से भूमध्य सागर तक निर्बाध पहुंच संभव हो सकेगी और यदि रूस दीर्घकालिक रूप से पश्चिम एशिया में अपनी भागीदारी को गहरा करना चाहता है, तो इसके लिए तुर्की की भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी। श्री पुतिन ने तुर्की को अपनी तरफ झुकाने के लिए कुछ समझौते किए हैं। दमिश्क के विरोध के बावजूद तुर्की द्वारा पिछले साल सीरिया के एक बड़े कुर्दिश शहर अफरीन पर हमला करने पर श्री पुतिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा, सीरिया को विद्रोहियों के हाथों से बहुत हद तक मुक्त करने के बाद भी रूस ने इदलिब में भी इसी तरह का कार्य नहीं किया।

इसका मतलब यह नहीं है कि रूस और तुर्की नए क्षेत्रीय सहयोगी बन गए हैं। उनके बीच अभी भी संरचनात्मक मुद्दे हैं। सीरिया में, जहाँ दोनों देश प्रतिद्वंद्वी पक्षों को पीछे छोड़ रहे हैं, संकट अनसुलझा है। तुर्की के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान को ऐतिहासिक रूप से अमेरिका के साथ गठबंधन किया गया है। लीबिया से लेकर इजराइल तक कई अन्य देशों में रूस और तुर्की के हित अलग-अलग हैं। लेकिन तुर्की ने जो अमिट संदेश भेजा है, वह यह है कि अमेरिका अब इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक अनिवार्य भागीदार नहीं है।

तुर्की ने नाटो को भी यह बताया है कि वह रूस के साथ एक रक्षा सौदा करते हुए संगठन के नाराजगी का जोखिम उठाने को तैयार है। अमेरिका को रूस की ओर जाते हुए तुर्की को अपनी तरफ करने के लिए या तो अपने तरीकों को सुधारना होगा या इसके खिलाफ जवाबी कार्यवाही करनी होगी। हालांकि, कोई कुछ भी कहे, लेकिन भव्य भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात पर यह श्री पुतिन की ही जीत है।

CS World
Committed To Excellence

अमेरिका-रूस-तुर्की

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में तुर्की ने कहा कि उसे रूस की एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की पहली खेप मिल गई है।
- यह खरीद नाटो सहयोगी अमेरिका की कई बार की चेतावनी के बाद भी आकार लेने में सफल रही है।
- इस कदम से तुर्की के अमेरिका के साथ रिश्तों में आये तनाव को बढ़ावा मिल सकता है। इससे पहले वाशिंगटन ने इस सप्ताह यह कह कर चेतावनी दी थी कि इसके ''वास्तविक और नकारात्मक'' परिणाम निकल सकते हैं, अगर अंकारा ने इस रूसी रक्षा प्रणाली की खरीददारी की।
- गौरतलब हो कि तुर्की के रूस से एस- 400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के फैसले के कारण अमेरिका ने तुर्की को एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने का फैसला त्याग दिया है।
- मौजूदा अमेरिकी कानूनों के अनुसार, कोई भी देश अगर रूस से बड़े रक्षा उपकरण खरीदता है, तो उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

नाटो क्या है?

- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) विभिन्न देशों का रक्षा सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 04 अप्रैल, 1949 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है।
- इसका उद्देश्य इसके सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा बनाए रखना है।
- नाटो के सदस्य देशों की संख्या आरम्भ में 12 थी, जो अब बढ़कर 29 हो चुकी है।
- नाटो का सबसे नया सदस्य देश मोंटेनिग्रो है। यह 5 जून, 2017 को नाटो का सदस्य बना था।
- नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल रक्षा खर्च के 70 प्रतिशत से अधिक है।

क्यों हुई थी इसकी स्थापना?

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इंकार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी।
- इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की कोशिश की, जो उस समय के शक्तिशाली सोवियत संघ के अतिक्रमण से रक्षा कर सके।

अन्य मुख्य बिंदु

- हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक कानून पारित किया है, जिससे भारत का दर्जा अमेरिका के नाटो सहयोगियों और इजराइल एवं दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान हो जायेगा।
- वित्तीय वर्ष 2020 के लिये पिछले सप्ताह पारित राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) में इस तरह का प्रस्ताव निहित था।
- यह विधेयक भारत को अमेरिका के नाटो सहयोगियों के बराबर का दर्जा देता है।
- गौरतलब हो कि अमेरिका ने भारत को 2016 में बड़ा रक्षा साझीदार माना था।
- इस विधेयक से भारत को अत्याधुनिक हथियार एवं संवेदनशील तकनीक देने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिन्हें सिर्फ नाटो देशों को ही सप्लाई किया जा सकता है।
- इससे भारत के साथ अमेरिका का रक्षा कारोबार का रास्ता आसान बन जाएगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को तब हुई, जब तत्कालीन सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इन्कार कर, अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी।
2. नाटो का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रो की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा बनाए रखना है।
3. नाटो का नीवनतम सदस्य मोंटेनिग्रो है, जिसके शामिल होने से इसके सदस्यों की संख्या 29 हो गई है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **In the reference to North Atlantic Treaty Organization, consider the following statements-**

1. NATO was established on 4 April, 1949 after Soviet Union of that time refused to remove its forces from Easten Europe and blocked Berlin in 1948 by violating international treaty.
2. The objective of NATO is to maintain political independence and military security of its members.
3. The newest member of NATO is Montengro, by which the number of NATO members became 29.

Which of the above statement are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 2
(c) 1 and 3 (d) All of above

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्न: विश्व राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता, हाल ही में तुर्की के सन्दर्भ में देखा जा सकता है, उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिनके कारण तुर्की, नाटो का महत्त्वपूर्ण सदस्य होने के बावजूद इसका झुकाव रूस की तरफ बढ़ता जा रहा है? (250 शब्द)

Q. Nothing can be permanent in world politics, which can be seen in reference to Turkey. Discuss the situations due to which Turkey is being inclined towards Russia, despite being a member of NATO. (250 Words)

नोट : 17 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Commit